



रोक लगाती है।

- धारा 4(1): यह अनविरत्य करता है कि उपासना स्थल की धार्मिक पहचान 15 अगस्त 1947 की स्थिति से अपरविरत रहनी चाहिये। धार्मिक चरित्र को बदलने का कोई भी प्रयास नषिद्ध है।
- धारा 4(2): यह वधियक 15 अगस्त 1947 से पहले किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन से संबंधित सभी चल रही कानूनी कार्यवाहियों को समाप्त करता है, तथा ऐसे स्थानों की धार्मिक स्थिति को चुनौती देने वाले नए मामलों को शुरू करने पर रोक लगाता है।
- धारा 5 (अपवाद): अयोध्या विवाद (बाबरी मसजिद-राम जन्मभूमि), जिसे अधिनियम से छूट दी गई।
  - अयोध्या विवाद के अलावा, अधिनियम में नमिनलखित को भी छूट दी गई है: कोई भी उपासना स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है, या प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत आने वाला कोई पुरातात्विक स्थल है।
  - ऐसे मामले जो पहले ही आपसी समझौते से सुलझा लिये गए हों या नपटा दिये गए हों।
  - अधिनियम के लागू होने से पहले हुए धर्मांतरण।
- धारा 6 (दंड): अधिनियम में उल्लंघन के लिये कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें तीन वर्ष तक का कारावास और उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने का प्रयास करने पर जुर्माना शामिल है।
- सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या: मई 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उपासना स्थलों के धार्मिक चरित्र की जाँच की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसी जाँच से धार्मिक चरित्र में कोई बदलाव न हो।

## उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के संबंध में क्या चर्चा है?

- न्यायिक समीक्षा को सीमित करना: इस अधिनियम को न्यायिक समीक्षा को सीमित करने तथा विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका की भूमिका को संभावित रूप से कमजोर करने के लिये चुनौती दी गई है।
- पूर्वव्यापी नरिधारित तथिः अधिनियम की पूर्वव्यापी नरिधारित तथिः 15 अगस्त 1947 है, को तर्कहीन बताते हुए इसकी आलोचना की गई है, जिससे कुछ धार्मिक समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन की संभावना है।
- कानूनी चुनौतियाँ: इस अधिनियम के विरुद्ध कई याचिकाएँ दायर की गई हैं, जिसमें याचिकाकर्त्ताओं ने तर्क दिया है कि यह हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को उपासना स्थलों पर पुनः दावा करने से रोकता है, जिनके बारे में उनका मानना है कि ऐतिहासिक शासकों द्वारा उन पर "आक्रमण" या "अतिक्रमण" किया गया था।
- कुछ विवादों के संदर्भ में छूट: राम जन्मभूमि-बाबरी मसजिद मामले को इस अधिनियम से छूट दिये जाने से असंगतता के साथ कुछ विवादों के चयनात्मक वधिकि उपचार की संभावना के बारे में चर्चा पैदा हुई है।
- सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि: इस अधिनियम से संबंधित वधिकि एवं सामाजिक बहसों कभी-कभी व्यापक सांप्रदायिक मुद्दों से संबंधित होती हैं।
  - आलोचकों का तर्क है कि इस अधिनियम को चुनौती देने से सांप्रदायिक तनाव (विशेषकर मसजिदों, मंदिरों एवं चर्चों जैसे संवेदनशील स्थलों के संदर्भ में) बढ़ने की संभावना है।
- धर्मनरिपेक्षता पर प्रभाव: इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक सद्भाव को बनाए रखते हुए भारत की धर्मनरिपेक्ष प्रकृति की रक्षा करना था, लेकिन इसके आलोचकों का मानना है कि यह अनजाने में ऐतिहासिक स्थलों पर कुछ धार्मिक समुदायों के दावों को दबाने की अनुमति दे सकता है, जिससे राष्ट्र के धर्मनरिपेक्ष ढाँचे को नुकसान पहुँचेगा।
- राजनीतिक और सामाजिक नरिहितार्थ: इस अधिनियम का प्रायः राजनीतिक और धार्मिक परिचर्याओं में उल्लेख किया जाता है, जिससे यह चर्चा उत्पन्न होती है कि धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल विभाजन को बढ़ावा देने या राजनीतिक कारणों के लिये समर्थन जुटाने के लिये किया जा सकता है।
  - वर्तमान में चल रहे कुछ विवादों के कारण सामाजिक अशांति उत्पन्न हुई है, धार्मिक स्थल पर दावों को लेकर वरिध प्रदर्शन और सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुए हैं, जो ऐसे मुद्दों पर गहरे सामाजिक विभाजन को दर्शाता है।

## आगे की राह

- कानूनी स्पष्टता की आवश्यकता: अधिनियम के प्रावधानों की अलग-अलग व्याख्याओं के साथ, उच्चतम न्यायालय द्वारा उपासना स्थल अधिनियम की प्रयोज्यता पर स्पष्ट और नरिश्चित दिशानरिदेश प्रदान करने की अत्यधिक आवश्यकता है।
- स्थानीय न्यायालय के अतरिक को रोकना: संवेदनशील धार्मिक मामलों में स्थानीय न्यायालयों के हस्तक्षेप की बढ़ती आवृत्ति, अधीनस्थ न्यायालयों की अधिकारिता सीमाओं की गहन जाँच की मांग करती है।
  - उच्चतम न्यायालय को ऐसे मामलों की नरिगरानी में अपनी भूमिका पर बल देना चाहिये जिनके व्यापक सामाजिक या राजनीतिक नरिहितार्थ हो सकते हैं।
- कानूनी मामलों का राजनीतिकरण न करना: धार्मिक स्थलों पर कानूनी चुनौतियों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखा जाना चाहिये, ताकि वैचारिक या चुनावी उद्देश्यों के लिये उनका दुरुपयोग न हो, न्यायपालिका की वरिश्वसनीयता और धार्मिक संस्थाओं की पवतिरता सुनरिश्चित हो सके।
- एकता पर ध्यान देना: राजनीतिक दलों और नागरिक समाज दोनों को विभाजन के बजाय एकता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वरिश्वत पर बल देने की आवश्यकता है, जो भारत को धर्म से परे एक साथ बाँधती है।

प्रश्न: धार्मिक स्थलों से संबंधित विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका की भूमिका, विशेष रूप से हाल ही में उपासना स्थल अधिनियम को मली चुनौतियों के आलोक में, का आकलन कीजिये।

